(a) whether a high level inter-ministerial meeting was held by the Prime Minister to find a solution to the current crisis in sugar industry; and

(b) if so, the details of the discussion which took place and the steps being taken to end the crisis?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Discussions have taken place in recent weeks, including in the context of a representation of the Maharashtra Rajya Sahakari Sakhar Karkhana Sangh, to address the difficulties encountered in the sugar industry following a general fall in prices.

2. The steps initiated to assist the industry include the creation of a Buffer Stock of 20 lakh tonnes for a period of one year involving an outgo of Rs. 412 crores from the Sugar Development Fund, in addition to which about Rs. 374 crores are expected to be released by banks on account of the Buffer Stock. Thus, about Rs. 786 crores would become available to the sugar industry for the payment of cane price dues to the farmers. The factory-wise allocation of the Buffer Stock (provisional) has been made and communicated to the sugar factories in January, 2003.

3. In order to further promote exports of sugar (to liquidate surplus stocks), it has been decided that neutralization of ocean freight disadvantage at the rate of Rs. 350 per tonne on export shipments of sugar would be reimbursed to sugar factories with effect from 14th February, 2003.

Arrears of sugarcane growers

†*155. DR. AKHILESH DAS:
SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU):††

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

†Question No. 147 and 155 were taken together.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Aimaduddin Ahmed Khan (Durru).

(a) whether cane growers have been agitating over recovery of arrears of their dues amounting to Rs. 11,000 crore from the sugar mills;

(b) if so, the details of the memoranda or representations received from the canegrowers during the past three months; and

(c) the steps taken by Government to ensure payment of their dues?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

There have been sporadic incidents of agitation by sugarcane growers in respect of payment of cane price due/cane price being offered by the sugar mills. Representations in this behalf have, *inter-alia*, been received from the Swantantra Bharat Paksh, Maharashtra and the Kissan Sangh, Budhana (Muzaffarnagar). The cane price dues for the last season 2001-2002 (as on 31.1.2003), as reported by the State authorities, stand at about Rs. 363.65 crores.

2. The following steps have been taken to facilitate speedy clearance of dues of sugarcane growers:

(i) A Buffer Stock of 20 lakh tonnes of sugar has recently been created, as a result of which the sugar factories would receive a subsidy amount of Rs. 412 crores (from the Sugar Development Fund) for the exclusive purpose of payment of cane price dues. In addition, about Rs. 374 crores would become available from the banks on account of additional margin money. Thus, about Rs. 786 crores would be available to the sugar factories to clear the payments of cane price dues to sugarcane growers.

(ii) The levy obligation of sugar factories has been reduced to 10% *w.e.f.* 1st March, 2002 to enable the factories to sell more sugar under free-sale quota in the open market.

(iii) The sugar factories have been extended temporary relief by way of permission to sell equivalent quantity of unlifted levy sugar stocks as free sale sugar in the open market. During

the sugar season 2001-2002, a quantity of 2,21,513.7 MTs of unlifted levy sugar stocks were allowed to be sold as free sale sugar.

(iv) Exports of sugar are being allowed without any quantitative restrictions and, to encourage such exports, the Sugar Development Fund (SDF), Act, 1982 and the SDF Rules, 1983 have been amended to neutralise the internal transport and ocean freight disadvantage.

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU): Thank you, Sir. The answer is silent on the steps to be taken for the recovery of arrears of the legitimate dues of the sugarcane growers from the sugar mills. I would like to know from the hon. Minister, since when are the payments pending and the reasons for non-payment of arrears. What are the legal remedies to help the poor sugarcane growers to get the remuneration for their hard labour? I would also like to request the hon. Minister that he may kindly inform the House if any specific measures have been taken, or are contemplated to help the agitating sugarcane growers.

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने यह जो सवाल पूछा है कि ।। हजार करोड़ रुपये के ड्यूज़ बाकी हैं तो यह बात सही नहीं है। ... (व्यवधान) जो टोटल ड्यूज़ अब बचे हैं वे 607 करोड़ रुपये के ड्यूज़ बचे हैं। उसमें भी पिछले साल के ड्यूज़ 363 करोड़ रुपये हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक: एक हजार करोड़ के टोटल हैं।

श्री शरद यादव: नहीं है, कौशिक जी। ....(व्यवधान) सभापति जी, सरकार के हाथ में जितनी सामर्थ्य है हमने 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया है। हम जो एक्सपोर्ट है उसके लिए आपके पोर्ट तक इंटरनल ट्रांसपोर्ट सबसिडी देते हैं। अब हमने 350 रुपया प्रति टन ओशन फ्रेट भी दे दिया। हमने पांच रुपये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाने का काम किया है। हमने हिन्दुस्तान में जो हमारे पास शूगर डिवलपमेंट फंड है...! जो देश का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देता है, हमने को-जनरेशन पर, मॉडर्नाइजेशन पर और इथनाल पर 6 परसेंट ब्याज देने का काम किया है। सभापति जी, केन्द्रीय सरकार के हाथ में जो सामर्थ्य थी, वह हमने काम किया है। हमने मॉडर्नाइजेशन वर्क के लिए एस॰डी॰एफ॰ को अमेंड करके किसान के ड्यूज के लिए, सिर्फ ड्यूज के लिए दिया है। सभापति जी, मैं स्टेट वाइज आंकड़े आप के सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह जानकारी विस्तार से सदन के सामने आनी चाहिए। मैं बताना चाहता कि यह पैसा सारे सूबों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वह एक जगह नहीं जा सकता। इसमें सब से ज्यादा ड्यूज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर

प्रदेश में सब से ज्यादा दिक्कत हो रही है। सभापति जी, आंध्र प्रदेश में 40 हजार करोड़ बफर स्टॉक से जाएगा, गुजरात में 50 करोड़ जाएगा, हरियाणा में 23 करोड़ जाएगा, कर्नाटक में 64 करोड़ जाएगा और महाराष्ट्र में 273 करोड़ बफर स्टॉक से जाएगा। महोदय, बिहार में 10 करोड़ जाएगा।

श्री प्रेम गुप्ता: बिहार का इतना कम क्यों है?

श्री शरद यादव: इसलिए कि वहां बफर कम है और यह नॉर्थ बिहार की शुगर मिलों के लिए गया है। मैं कौशिक जी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 163 करोड़ गया है यानी जो हमारे हाथ में था वहां अपना पूरा खजाना खाली कर के किसानों के पुराने ड्यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है।

श्री सभापति: बहुत अच्छा।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति जी, मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने 786 करोड़ रुपया बफर स्टॉक और बैंकों के जरिए से दिलाया है और ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था की है। माननीय मंत्री जी को शायद जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार की सिक मिलें चलती हैं-एक प्राइवेट, दूसरी कॉर्पोरेशन की और कोऑपरेटिव्स की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही चलती हैं। महोदय, ये मिलें महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह की नहीं हैं और जो पैसा बाकी है वह ज्यादातर फैक्ट्रीज कॉरपोरेशन या कोऑपरेटिव्स का है। प्राइवेट वालों के पैसों के मामले में आप ने कुछ तरक्की की है, लेकिन कॉर्पोरेशन की मिलों पर और कोऑपरेटिव्स की मिलों का सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया है और उत्तर प्रदेश में तो स्थिति यह है जिसे मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज तक भी किसान को पता नहीं है कि इस साल वह जो गन्ना दे रहा है, उसका उसे कितना पैसा मिलेगा। इसलिए माननीय मंत्री बताएं कि कार्पोरेशन की फैक्ट्रियों पर और कोऑपरेटिव की फैक्ट्रियों पर जो पैसा है, उसका कब तक भुगतान होगा जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। साथ ही पिछले सालों का जो ब्याज का पैसा है, उसका भुगतान कब होगा? तीसरे, किसान को गन्ने के खरीदी मूल्य का भी पता चले कि वह किस भाव खरीदा जा रहा है।

श्री शरद यादव: महोदय, संविधान के अंतर्गत जो हमारे हाथ में काम था, केन्द्रीय सरकार के हाथ में काम था, उसे करने का हम ने काम किया है। इतिहास में इस तरह का काम पहले हुआ हो तो निश्चित तौर पर हम जो कह रहे हैं, मैं उस को मान सकता हूं। हां, काम बंटे हुए हैं। वहां की जो शुगर मिलें हैं, वहां की जो कोऑपरेटिव्स हैं उन के बारे में हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है, लेकिन हम ने आप की भावनाओं को लगातार राज्यों को पहुंचाने का काम किया है।

श्री मोती लाल वोरा: महोदय, राज्य सरकार एक्शन ले सकती है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश में किसानों को उनके गन्ने का मूल्य नहीं

मिल रहा है, केवल पर्चियां मिल रही हैं।...(व्यवधान)... मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद आज भी किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति: प्रश्न इतना सा था कि बकाया कितना है?

श्री शरद यादव: सभापति जी, मोती लाल वोरा जी जो कह रहे हैं, इसके पहले हम दस बार सूबों की सरकार से, एक सरकार से नहीं सब सूबों की सरकारों से इंटरएक्शन करते हैं। उनको कहते भी हैं, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि जो हमारे हाथ में है वह हम करते हैं, हम उनको सलाह-मशविरा दे सकते हैं, उनको परस्यू कर सकते हैं।

Cheap Nepalese vanaspati

*148. SHRI RUMANDLA RAAMACHANDRAYYA:††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether he has convened an emergency meeting alongwith the Ministries of Finance, Commerce and Health to look into the onslaught of cheap Nepalese vanaspati putting survival of the Rs. 5,000 crore domestic industry into question;

(b) if so, what was the main agenda of meeting;

(c) whether all the vanaspati units in Eastern India have been closed down following Nepalese dumping triggered by Government's policy;

(d) what decision has been taken to meet the situation; and

(e) to what extent this decision has helped in improving the vanaspati units in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI V. SREENIVASA PRASAD): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) A meeting was convened in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rumandla Raamachandrayya.